सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः `02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, बुधवार, 24 दिसंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 241, पृष्ठः 8+4

इनसाइड कट्टरपंथ और चरमपंथ की गिरफ्त में बांग्लादेश » Pg12

अमृतसर में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ हवलदार का निधन

» Pg04

सुप्रीम कोर्ट जाएगी उन्नाव रेपकांड की पीड़िता

आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद निलंबित कर जमानत दी

» पीड़ित परिवार दिल्ली में धरने पर बैठा, पुलिस ने जबरन हटाया

» मुख्य संवाददाता/स्वराज इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा, दिल्ली में ही रहेगा, किसी तरह की धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक जमानत मिलने के बाद भी सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि

वह अभी पीड़िता के पिता की हत्या मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद रेप पीड़िता और उसके परिवार में गहरा भय और तनाव का माहौल है। पीड़िता ने कहा कि जब जमानत का फैसला सुना तो वह स्तब्ध रह गई और पलभर के लिए आत्महत्या करने का विचार आया। पीड़िता ने कहा कि अब उसकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है और न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पीड़िता की मां ने भी हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि परिवार लगातार डर के साए में जी रहा है।

पीड़िता पक्ष ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट खुलते ही जमानत के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी और न्याय के लिए हर कानूनी विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्नाव रेप कांड देश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रहा है। इस मामले ने न केवल राजनीतिक हलचल पैदा की थी, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे।

अब जमानत के इस फैसले ने पीड़िता की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ा दी है। सामाजिक संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील मामलों में पीड़ित पक्ष का मनोवैज्ञानिक दबाव भी न्यायिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जाना चाहिए। कई संगठनों ने सरकार और पुलिस से पीड़िता परिवार को मजबूत सुरक्षा देने की मांग की है। अब इस मामले का अगला बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं।

इसरो ने रचा इतिहास, अब अंतरिक्ष से मिलेगा मोबाइल का नेटवर्क

16 मिनट में 6100 किलो वजनी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। इसरो ने इस वर्ष के आखिरी मिशन के साथ इतिहास रच दिया है। दरअसल इसरो ने भारत की धरती से अब तक के सबसे बड़े और सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। यह अमेरिका की एक कंपनी का उपग्रह है, जिससे मोबाइल नेटवर्क और अधिक बेहतर होगा। इस मिशन से वाणिज्यिक क्षेत्र में इसरो की पकड़ और मजबूत होगी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष के अपने अंतिम मिशन में इसरो ने सबसे भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह पूरी तरह से वाणिज्यिक प्रक्षेपण

मिशन के अंतर्गत अमेरिका की कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल के 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 संचार उपग्रह को 520 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में मात्र 16 मिनट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।

इसरो ने इस प्रक्षेपण के लिए अपने एलवीएम–3 रॉकेट का उपयोग किया, जिसे इसकी भारी भार वहन क्षमता के कारण फबाहुबलीफ रॉकेट भी कहा जाता है। यह इस प्रक्षेपण यान की छठी उड़ान थी और वाणिज्यिक मिशन के लिए तीसरी।यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर किया गया। इसरो के अनुसार लगभग 16 मिनट की उड़ान के बाद संचार उपग्रह रॉकेट से अलग होकर करीब 520 किलोमीटर की ऊँचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हो गया। यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) और अमेरिका की एएसटी स्पेसमोबाइल (एएसटी एंड साइंस एलएलसी) के बीच हुए वाणिज्यिक समझौते का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी

इसरो की इस सफलता पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, फभारत के युवाओं की शक्ति से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अधिक आधुनिक व प्रभावी बन रहा है। एलवीएम–3 ने भरोसेमंद भारी भार वहन क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए नींव मजबूत हो रही है। साथ ही वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का विस्तार और वैश्विक साझेदारियों को मजबूती मिल रही है। यह बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद लाभकारी है।

क्यों खास है इसरो का यह मिशन

इस सफल प्रक्षेपण की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थिति और मजबूत हुई है। ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है। यह भारत की धरती से प्रक्षेपित होकर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी वाणिज्यिक संचार उपग्रह है।

भारत अपने एलवीएम–3 प्रक्षेपण यान के माध्यम से चंद्रयान–2, चंद्रयान–3 और वैश्विक स्तर पर उपग्रह इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली वन वेब कंपनी के उपग्रहों के प्रक्षेपण को पहले ही सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। वन वेब मिशन के तहत इसरो ने एलवीएम–3 से दो बार में कुल 72 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए थे।

ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 उपग्रह अगली पीढ़ी की तकनीक पर आधारित प्रणाली का हिस्सा है। यदि यह उपग्रह पूरी तरह सफल रहता है और कंपनी के सभी परीक्षण सफल होते हैं, तो इसके माध्यम से सीधे 4जी और 5जी स्मार्टफोन पर सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को किसी अतिरिक्त एंटीना या विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में मोबाइल फोन को 4जी या 5जी नेटवर्क से जुड़ने के लिए मोबाइल टावरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

तीन वर्षों के ठहराव के बाद टूटा वरासत का गतिरोध

कानपुर नगर में 174 शस्त्र लाइसेंस जारी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।कानपुर नगर में शस्त्र लाइसेंस की वरासत से जुड़े मामलों में इस वर्ष बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2022, 2023 और 2024 में जहां एक भी वरासत शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हो सका था, वहीं चालू वर्ष में अब तक 174 प्रकरणों का निस्तारण कर लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इससे वर्षों से लंबित मामलों में प्रतीक्षारत परिवारों को राहत मिली है। इस वर्ष की शुरुआत में जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे आवेदक जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे थे, जो अपने परिजनों के निधन के बाद उनकी स्मृतियों और पारिवारिक धरोहर को संरक्षित रखने के उद्देश्य से शस्त्र लाइसेंस की वरासत की मांग कर रहे थे। कई प्रकरण वर्षों से लंबित थे और आवेदक बार-बार कार्यालयों के चक्कर काट चुके थे। डीएम ने इन प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ संज्ञान में लिया गया और नियमानुसार समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

सभी लंबित आवेदनों की क्रमवार समीक्षा कर दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस जारी किए गए। इन 174 प्रकरणों में रिवाल्वर एवं पिस्टल के 91, डीबीबीएल व एसबीबीएल गन के 57 तथा एनपी बोर राइफल के 26 मामले शामिल हैं।

वरासत के स्वरूप की बात करें तो पिता की शस्त्र विरासत पुत्र एवं पुत्री को 128 प्रकरणों में, बाबा की विरासत पौत्र को 16 प्रकरणों में, पति की विरासत पत्नी को 24 प्रकरणों में, ससुर की विरासत बहू को तीन प्रकरणों में तथा भाई की विरासत भाई को तीन प्रकरणों में हस्तांतरित की गई।

वरासत लाइसेंस प्राप्त करने वाले विवेक पाठक ने बताया कि पिता के निधन के बाद उनका आवेदन लंबे समय से लंबित था और कई प्रयासों के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन इस वर्ष दस्तावेजों की जांच के बाद लाइसेंस जारी हो गया।

एक अन्य लाभार्थी प्रीति सिंह, जिन्हें पति की वरासत में लाइसेंस मिला, ने कहा कि स्पष्ट प्रक्रिया और समयबद्ध निर्णय से उन्हें बड़ी राहत मिली।अधिकारियों के अनुसार इस पहल से न केवल लंबित मामलों का समाधान हुआ है, बल्कि शस्त्र लाइसेंस वरासत की प्रक्रिया में विश्वास और संवेदनशील प्रशासन की छवि भी सुदृढ़ हुई है।

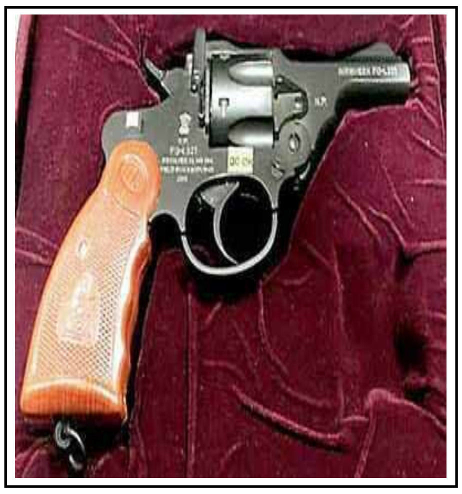

वर्षवार	स्थिति
2022-	0
2023-	0
2024-	0
2025 (अब तक)-	174

श्रेणीवार शस्त्र

रिवाल्वर / पिस्टल- 91

डीबीबीएल / एसबीबीएल गन- 57

एनपी बोर राइफल - 26

रिश्ते के आधार पर वरासत

पिता - पुत्र / पुत्री - 128

बाबा - पौत्र -16

पति - पत्नी - 24

ससुर - बहू - 3

भाई - भाई - 3

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि नागरिकों से जुड़ी वैधानिक प्रक्रियाएं अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में आए कई आवेदक अपने प्रियजनों की स्मृतियों से जुड़ी धरोहर को सुरक्षित रखने की भावना के साथ सामने आए थे और प्रशासन ने नियमों के दायरे में रहते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान किया। आगे भी सभी वैध प्रकरणों का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

कानपुर में इस बार 1.78 लाख नए मतदाता

» पंचायत चुनाव में अंतिम सूची का जिला प्रशासन ने प्रकाशन कर दिया है

ब्लाक	बढ़े मतदाता	कटे मतदाता
ककवन-	53,861	4341
कल्याणपुर-	1,38,937	21681
घाटमपुर-	1,72,522	19355
चौबेपुर -	1,15,388	10220
पतारा -	1,17,171	11362
बिल्हौर -	1,45,312	13471
भीतरगांव-	1,41,576	17627
बिधनू -	1,51,119	15134
शिवराजपुर -	1,02,307	10164
सरसौल -	1,46,267	23392

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पूरा हो गया है। मंगलवार को अंतिम सूची का जिला प्रशासन ने प्रकाशन कर दिया है। जिले में इस बार 1.78 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। मतदाता सूची में बड़े स्तर पर संशोधन करते हुए 1.46 लाख नाम हटाए भी गए हैं। इस बार पंचायत चुनाव में 12 लाख 84 हजार मतदाता गांव की सरकार चुनेंगे। इसके अलावा 24.54 हजार मतदाताओं के नाम और पते में सुधार किया गया है।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील द्विवेदी ने बताया कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन हो गया है। अब 24 दिसंबर से 30 दिसबर तक दावा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी ताकि अंतिम सूची त्रुटिरहित बनाई जा सके। अंतिम सूची का प्रकाशन फरवरी में होगा। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले की 590 ग्राम पंचायतों में कुल 12.53 लाख मतदाता पंजीकृत थे। इस बार मतदाताओं की संख्या 12.84 लाख तक पहुंच गया है।

नाले पर कब्जा वैध करने का सामने आया सरकारी जुगाड़

नाले की जगह प्लॉटिंग, ग्राम समाज की सड़क पर खुदवा दी गई नाले की जगह नाली

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। चौबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत राय गोपालपुर में नाले की जमीन पर कब्ज़ा कर अवैध प्लाटिंग का मामला अब और गंभीर हो गया है। स्वराज इंडिया द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे की खबरों का संज्ञान लेते हुए एसडीएम बिल्हौर ने कार्रवाई तो शुरू कर दी, लेकिन इस कार्रवाई के भीतर भी भ्रष्टाचार की बू साफ महसूस हो रही है। सूत्रों के अनुसार कानूनगो मुकेश दुबे मौके पर पहुंचे और नाले की पुन: खुदाई की प्रक्रिया करवाई, लेकिन यहां बड़ा खेल सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां पहले नाला स्थित था, वह जमीन वर्तमान में भू–माफिया पंकज दुबे के कब्जे में है और वहां चल रही प्लाटिंग को बचाने के लिए नाले की जगह बदल दी गई। आरोप है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू–माफिया से सांठगांठ करते हुए ग्राम समाज की सड़क की जमीन पर नाली रूपी नाला दिखा दिया, जबकि असली नाले की जमीन प्लाटिंग के अंदर समा चुकी है और उस पर बाउंड्री भी खड़ी कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया नाले की वास्तविक जमीन को बचाने के बजाय भू–माफिया को संरक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। गांव के लोगों ने उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच, वास्तविक नाले की बहाली और दोषी राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

आरोपी पंकज दुबे

सीवर लाइन डालने में हो रही लापरवाही

दक्षिण कानपुर

महापौर की अध्यक्षता में सीवर लाइन कार्यों को लेकर अहम बैठक, पार्षदों ने जताई नाराज़गी

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। महापौर की अध्यक्षता में दक्षिण क्षेत्र के जोनङ्ग3 एवं जोनङ्ग5 अंतर्गत 13 वार्डों में जल निगम द्वारा डाली जा रही सीवर लाइनों को लेकर नगर निगम मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वार्ड संख्या 7, 9, 21, 34, 45, 51, 55, 65, 70, 72, 77, 82 एवं 87 के पार्षदों के साथ जल निगम एवं जलकल विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में पार्षदों ने एक स्वर में आरोप लगाया कि सीवर लाइन डालने के कार्यों की उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं दी जा रही है। न तो कार्य की समय-सीमा बताई जाती है और न ही यह स्पष्ट किया जाता है कि कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है। पार्षदों ने बताया कि कई गलियों में 200 एमएम की सीवर लाइन डाली जा रही है, जबकि पूर्व में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 200 से 250 एमएम तक की लाइनें डाली जा चुकी हैं। आबादी बढ़ने और सीवर तथा बरसाती पानी के एक साथ बहाव के कारण भविष्य में इन लाइनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे सीवर ध्वस्त होने की आशंका है और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।

पार्षदों ने यह भी आपत्ति जताई कि विकसित क्षेत्रों में जेसीबी मशीनों से खुदाई की जा रही है, जबकि इन क्षेत्रों में पहले से सीवर, पानी, गैस एवं मोबाइल की लाइनें मौजूद हैं। मशीनों से खुदाई के कारण इन लाइनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने मांग की कि कार्य मैनुअल कराया जाए और पुरानी लाइनों से छेड़छाड़ किए बिना नए स्थान पर सीवर लाइन डाली जाए। इसके अलावा कई नई सड़कों को खोद दिए जाने से नगर निगम के ठेकेदारों का भुगतान भी फंस गया है।नौरैयाखेड़ा एवं दबौली क्षेत्रों में घरेलू जल-मल नहर में जाने का मुद्दा उठाते हुए पार्षदों ने पहले इन क्षेत्रों में कार्य शुरू कराने की मांग की। साथ ही अविकसित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने, सीवर चैंबर की दूरी 30 मीटर से कम रखने, पुराने क्षतिग्रस्त सम्पवेल के स्थान पर नए सम्पवेल बनाए जाने की भी मांग रखी गई।

बैठक में महापौर ने सीवर लाइन कार्य की निविदादाता फर्म एलसी इन्फ्रा के महाप्रबंधक पंकज गज्जर एवं जल निगम अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बिना पार्षदों को सूचित किए कोई कार्य न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित 13 वार्डों में पुरानी लाइनों को न छुआ जाए और न ही क्षतिग्रस्त किया जाए। प्रत्येक वार्ड का कार्य-नक्शा पार्षदों को उपलब्ध कराया जाए और बिना सूचना के कोई सड़क न खोदी जाए। किस वार्ड में कब से कब तक कार्य होगा, इसकी सूचना नगर निगम के मुख्य अभियंता सिविल को अनिवार्य रूप से दी जाए।

महापौर ने कहा कि पूर्व में जेएनयूआरएम के अंतर्गत हुए कार्यों से जनता आज भी परेशान है। जल निगम की लापरवाही के कारण पानी की लाइनें बार-बार क्षतिग्रस्त हुई, जिससे उन्हें पंद्रहवें वित आयोग की धनराशि से लोहे की पाइप लाइन डलवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि कार्य ऐसा हो जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सके।

महाप्रबंधक जलकल आनंद कुमार त्रिपाठी ने डीपीआर में प्रस्तावित सीवर लाइन की साइज पर असहमति जताते हुए कहा कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए कम से कम 30 वर्षों के हिसाब से क्षमता तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रतनलाल नगर जैसे क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन बन रहे हैं, जहां 200 एमएम की सीवर लाइन पर्याप्त नहीं होगी।बैठक में पार्षद डॉक्टर अखिलेश वाजपेयी, सुधीर यादव, अलिल यादव, सतीश यादव, धीरेन्द्र कुमार सोनकर, योगेंद्र शर्मा, संतोष साहू सहित जल निगम एवं जलकल के अधिकारी एवं एलसी इन्फ्रा के परियोजना प्रमुख शैलेश कुमार सिंह उपस्थित रहे।

सड़क खोद देते हैं, नगर निगम के पत्रों का जवाब भी नहीं देते

नगर निगम के मुख्य अभियंता सिविल सैय्यद फरीद अख्तर जैदी ने बताया कि बिना अनुमति सड़क खोदने पर जल निगम को नोटिस दिया गया है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि हर वार्ड में पार्षद, जल निगम और जलकल अधिकारियों का संयुक्त समूह बनाया जाए, ताकि मौके पर ही समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही कार्य स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने और अधिकतर कार्य सड़कों के बजाय फुटपाथ पर कराने पर जोर दिया।अधीक्षण अभियंता जल निगम राजेंद्र सिंह ने बताया कि दक्षिण क्षेत्र में 414 करोड़ रुपये की लागत से 440 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जानी है। इसमें 324 किलोमीटर 200 एमएम, 64 किलोमीटर 250 एमएम, 11 किलोमीटर 300 एमएम तथा एसटीपी कनेक्शन हेतु 1800 एमएम की लाइन शामिल है। सीवर लाइन से लगभग 43,760 कनेक्शन होंगे, जिससे करीब 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि जहां साइज बदलने का मामला है, वहां तकनीकी सर्वे कराकर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा और महापौर एवं पार्षदों के निर्देशानुसार कार्य कराया जाएगा।

चित्र पर तिलक कर मनाई अटल जी की जयंती

» राजनीति में सुचिता और प्रमाणिकता के प्रतिबिंब थे अटल जी

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सीएनसी स्कूल गांधीनगर कानपुर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के जन्म दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ नन्हे मुन्ने बच्चों ने अटल जी के चित्र पर तिलक कर किया ।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर दिवाकर मिश्र ने अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अटल जी का कानपुर से जुड़ाव अत्यधिक रहा है। उन्होंने स्थानीय डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र परा स्नातक एवं विधि स्नातक की परीक्षा पास की थी। प्रारंभ से ही अटल जी मेधावी थे।

अटल जी को श्रद्धांजलि सच्ची तब होगी जब आप सभी विद्यार्थी मेधावी बनेंगे।राजनीति में सुचिता और प्रमाणिकता के प्रतिबिंब अटल जी थे । अटल जी केवल राजनेता ही नहीं वह कवि हृदय सम्राट भी थे।

इस अवसर पर विद्यार्थियों के बीच मिष्ठान वितरण किया गया।

समारोह में प्रमुख रूप से रूबी जायसवाल, गायत्री प्रजापति, कार्तिक दिवाकर, नेत्रा मिश्रा, धैर्य कुमार, चंदन कुमार, मिस्टी, वंश कुमार कश्यप, रमन कुमार, नंदिनी प्रजापति, दिव्या शर्मा, लक्ष्य जायसवाल आदि ने सहभाग किया।

प्रकाश पर्व पर मोतीझील में सख्त सुरक्षा, पुलिस ने बनाई रणनीति

» नगर कीर्तन से लेकर पूरे आयोजन स्थल तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी

» डीसीपी ने आयोजकों से समन्वय बनाए रखने और तय रूट पालन करने की अपील की

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। प्रकाश पर्व के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने सेंट्रल जोन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की। यह पर्व 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक थाना स्वरूपनगर क्षेत्र स्थित मोतीझील में आयोजित किया जाएगा।

गोष्ठी में श्री गुरु सिंह सभा के आयोजकों को बताया गया कि प्रकाश पर्व के तहत लाटूश रोड स्थित गुरुद्वारे से मोतीझील तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा।नगर कीर्तन व मुख्य कार्यक्रम को सुरक्षित, शांतिपूर्ण व व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, ट्रैफिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।डीसीपी सेंट्रल ने आयोजकों से आपसी समन्वय बनाए रखने, निर्धारित रूट का कड़ाई से पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। गोष्ठी में एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह, थाना प्रभारी अनवरगंज, थाना प्रभारी स्वरूपनगर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि प्रकाश पर्व के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु निर्भय होकर कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

कपड़ा मार्केट में लाखों की चोरी करने वाला गिरफ्तार

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बादशाहीनाका थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई जनपदों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कपड़ा मार्केट में शटर काटकर करीब साढ़े सात लाख रुपये की चोरी को अंजाम दिया था। आरोपी को जेल भेज दिया है।थाना बादशाहीनाका पुलिस के अनुसार शातिर अपराधी हमवीर सिंह उर्फ करू ने जनरलगंज कपड़ा मार्केट में एक साड़ी की दुकान का शटर काटकर करीब साढ़े सात लाख रुपये की चोरी की थी। पूछताछ में आरोपी ने पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है।गिरफ्तार आरोपी करू जनपद कासगंज का रहने वाला है और उस पर कानपुर, कासगंज, हाथरस और फतेहगढ़ समेत कई जनपदों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

अमृतसर में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ हवलदार का निधन

» एसीपी-इंस्पेक्टर सहित पुलिस बल ने दी श्रद्धांजलि, युवाओं ने तिरंगा लेकर निकाली अंतिम यात्रा

गांव पहुंचते ही उमड़ा , जनसैलाब, तिरंगे में लिपटे वीर को नम आंखों से अंतिम विदाई

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। अमृतसर में तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हवलदार विनोद कुमार पाल का पार्थिव शरीर बुधवार को जैसे ही उनके पैतृक गांव बिल्हौर के बहरामपुर पहुंचा, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तिरंगे में लिपटे वीर जवान को देखते ही परिजनों का धैर्य टूट गया। पत्नी, बेटे और बेटी शव से लिपटकर फूट-फूट कर रो पड़े। ड्यूटी के दौरान अचानक हृदयगति रुकने से रविवार देर रात उनका निधन हो गया था। साथी जवान तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके।

वीर जवान की अंतिम यात्रा में क्षेत्र के लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। पूरे रास्ते भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें के नारों से माहौल गूंजता रहा। गांव के पास गंगा घाट पर बीएसएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी। बेटे मयंक ने मुखाग्नि दी।

पहले कानपुर, फिर गांव लाया गया पार्थिव शरीर

परिवार वर्तमान में कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के मिर्जापुर में रह रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अमृतसर से पार्थिव शरीर पहले कानपुर लाया गया। वहां से सैन्य वाहन द्वारा बहरामपुर गांव पहुंचाया गया। जैसे ही सेना का वाहन गांव में दाखिल हुआ, हर आंख नम हो गई।

पत्नी को फोन पर मिली मौत की सूचना, बेसुध होकर गिरीं

रविवार रात बीएसएफ मुख्यालय से जवान के निधन की सूचना फोन पर दी गई। कॉल पत्नी मीरा पाल ने रिसीव की। खबर सुनते ही वह बेसुध होकर गिर पड़ीं। मां की आवाज सुनकर बेटे-बेटी कमरे में पहुंचे और पूरे घर में कोहराम मच गया। बेटे मयंक ने बताया कि रविवार शाम करीब आठ बजे वीडियो कॉल पर पिता से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि वे बिल्कुल ठीक हैं और जल्द छुट्टी लेकर घर आएंगे। छह महीने पहले फैटी लीवर की समस्या थी, लेकिन इलाज के बाद सब सामान्य हो गया था।

बेटी बोली पढ़ाई को लेकर आखिरी बार हुई थी बात

बेटी गीतांशी ने बताया कि रविवार को ही पिता से बात हुई थी। उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा था। दीपावली पर पापा घर आए थे। अब उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई।

परिवार की सरकार से मांग

परिजनों ने सरकार से मांग की है कि दोनों बच्चों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। गांव में शहीद स्मारक बनाया जाए तथा एक सड़क का नाम वीर हवलदार विनोद कुमार पाल के नाम पर रखा जाए।

एसीपी-इंस्पेक्टर सहित पुलिस व स्थानीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

वीर जवान की अंतिम विदाई में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह एरोली और इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके अलावा क्षेत्र के कई

जनप्रतिनिधि व स्थानीय नेता अंतिम यात्रा में शामिल हुए और परिजनों को ढांढस बंधाया।

स्विफ्ट कार्यक्रम के तहत बिल्हौर में चला 'कोई मतदाता न छूटे' अभियान

» अरौल स्थित जीपीआरडी महाविद्यालय में हुआ जागरूकता आयोजन

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को स्विफ्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 'कोई भी मतदाता न छूटे' अभियान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अरौल स्थित जीपीआरडी महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 209, बिल्हौर के निर्देशन में किया गया।जागरूकता बैठक में महाविद्यालय परिवार के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही लोकतंत्र की मजबूती में मतदान की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उप जिलाधिकारी बिल्हौर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर पात्र सभी युवाओं को नए मतदाता के रूप में पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वयं के साथ-साथ समाज के उन नागरिकों को भी मतदान सूची से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, जिनके नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रशासन की ओर से विद्यालय प्रशासन, छात्र-छात्राओं एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

अपना दल (एस) ने वकीलों के धरने को दिया समर्थन

उप निबंधक कार्यालय स्थानांतरण के विरोध में चल रहा धरना

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। उप निबंधक कार्यालय स्थानांतरण के विरोध में चल रहे वकीलों के धरने को अपना दल (एस) पार्टी का समर्थन मिला। अनुसूचित मोर्चा के कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष अर्जुन दिवाकर मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ धरनास्थल पर पहुँचे और अधिवक्ताओं को समर्थन पत्र सौंपा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। अर्जुन दिवाकर ने कहा कि वकीलों की मांगें जनहित से जुड़ी हैं और पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। आपको बता दें कि अधिवक्ता पिछले 12 दिनों से कलम बंद हड़ताल पर हैं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक कोई लिखित जवाब नहीं मिलता है तब तक यह धरना जारी रहेगा।

सम्पादकीय

चीन की कामयाबी से सबक ले रोकें प्रदूषण

देश-दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फॉम-होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक्यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे।हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड-ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो-बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अधिक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल-रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव-सफाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है।

लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए विशेष बजट की भी व्यवस्था हो। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली की तीन सौ किमी की परिधि में ग्यारह कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स हैं, जिन्हें सर्वाधिक प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। बहरहाल, दीर्घकालिक नीति बनाने व फैसलों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

जी-राम-जी' बनाम मनरेगा की तार्किकता का प्रश्न

ज्योति मल्होत्रा

सत्तापक्ष के पास हमेशा से संख्या बल रहा है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि 'जी-राम-जी' मनरेगा की जगह ले लेगा, भले ही कांग्रेस ने संसद के बाहर लगी गांधी की प्रतिमा के सामने कितने भी विरोध प्रदर्शन किए हों।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसद की बजाय इथियोपियाई संसद को चुना, विपक्ष के नेता राहुल गांधी म्यूनिख में एक फैंसी बाइक चलाते हुए देखे गए, जबकि उन्हें लोकसभा में बने रहकर राष्ट्र को दरपेश अनेकानेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी, वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर राज्यसभा की बजाय इस्राइल में थे। गत सप्ताह, शीतकालीन सत्र में सदन से तीन प्रमुख नेताओं के नदारद रहने पर, आप हैरान होंगे - क्या यह संसद की प्रासंगिकता का प्रश्न नहीं है?यह एक अल्पकालीन सत्र था, हालिया इतिहास के सबसे छोटे सत्रों में से एक। लेकिन इसमें लाए गए महत्वपूर्ण कानूनों की कोई कमी नहीं थी, इनमें सबसे अहम है, प्रति परिवार, प्रति वर्ष 125 दिनों के काम के लिए मजदूरी से संबंधित 'जी-राम-जी कानून', जिसको सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले पारित किया गया। चूंकि सत्तापक्ष के पास हमेशा से संख्या बल रहा है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि 'जी-राम-जी' मनरेगा की जगह ले लेगा, भले ही कांग्रेस ने संसद के बाहर लगी गांधी की प्रतिमा के सामने कितने भी विरोध प्रदर्शन किए हों।

विपक्ष ने भी यह पूछा कि कानून का नाम क्यों बदला जा रहा है। क्यों महात्मा गांधी के संक्षिप्त नाम के पहले दो अक्षर एमजी को राम से बदला जा रहा है, जबकि सरकार वर्णमाला के किसी भी अन्य शब्द को चुन सकती थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कानून को पेश करने के काम की अगुवाई, अन्यथा बढ़िया ढंग से की, उनके पास कोई उचित जवाब नहीं था। संसद में गांधी के आदर्श 'राम राज्य', स्वयं भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में भाषणों की गूंज सुनाई दी- लेकिन इस बात का कोई असल कारण नहीं बताया गया कि मनरेगा में बदलाव क्यों किया गया, न तो बातों में और न ही कार्यरूप में।

दिलचस्प बात यह है कि 'जी-राम-जी' का एक पिछला स्वरूप भी था, जिसका जीवनकाल 24 घंटे का था। इसे 'पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार योजना' का नाम दिया गया था, जो कि अंग्रेजी में लिखे मूल नामकरण, 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' का नज़दीकी हिंदी अनुवाद था। साफ है, भाजपा ने महात्मा गांधी, या पूज्य बापू को प्रतीकात्मक रूप से राम के नाम से बदलने का फैसला किया।

क्यों? वह हम नहीं जानते। कुछ लोग कहेंगे, आखिर नाम में क्या रखा है? कुछ लोगों का जवाब होगा, सब कुछ है। कि बापू की मृत्यु के लगभग 78 साल बाद, उनका नाम मिटाने की कोशिश है, जिसकी अहमियत को शायद, हम समझ भी न पाएं। गांधी मां-बेटी की जोड़ी ने नारे लगाए और सदन के बाहर मार्च किया, लेकिन कुछ हद तक यह सब आधा-अधूरा था। इस बीच, 'गांधी परिवार' के उत्तराधिकारी म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू की साझेदारी में बन रही टीवीएस-450 सीसी मोटरसाइकल चलाते दिखे। हालांकि, पार्टी के कहे मुताबिक, वे वहां इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के नेताओं से 'पार्टी की विचारधारा को विस्तार देने की रणनीतियों' पर चर्चा करने के वास्ते गए हैं। सवाल यह बना हुआ है कि किस देश में।

कुछ ही महीने पहले, राहुल ने बिहार चुनाव में कांटे की लड़ाई लड़ने की बजाय, 'पार्टी का विस्तार' करने के लिए दक्षिण अमेरिका जाने का फैसला किया था। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते उनके पदचिन्ह जर्मनी में ही बने रहेंगे। अवश्य ही, जिस किस्म की दिखावेबाजी आजकल विपक्ष कर रहा है, वह आत्मघाती जैसा है। निश्चित तौर पर, अगर यह सब थोड़ा और समय तक चलता रहा, तो जल्द ही कांग्रेस पार्टी को पुनः एकजुट रखना न केवल असंभव होगा, बल्कि घातक भी होगा।

हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री संसद की गहमागहमी में इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरों के लिए तैयार था—यूके के बाद दूसरी संधि— लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इथियोपिया और जॉर्डन के दौरे इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे। जॉर्डन नरेश हुसैन दो साल पहले ही भारत की यात्रा पर आए थे; वापसी दौरा किसी और वक्त भी रखा जा सकता था। जहां तक इथियोपिया की बात है, जिस संसद भवन में मोदी को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, भले ही वह चीनियों ने न बनाया हो, लेकिन पास के अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय उन्होंने ही बनाया है। दरअसल, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अफ्रीका भर में 15 मुल्कों के संसद भवन बनाए हैं, लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी है।

बहरहाल, गत सप्ताह मोदी को इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले—ये उनके 28वें और 29वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। इस बीच, जब राहुल जर्मनी में छुट्टियां मना रहे थे तो एक कांग्रेस ने बिना सोचे-समझे सदन के बीचों-बीच आकर हंगामा किया। लेकिन यह तृणमूल कांग्रेस है, न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने गुरुवार की रात को दिल्ली की तीखी ठंड में 'जी-राम-जी' पारित होने के विरोध में संसद की सीढ़ियों पर रात्रि के अधिकांश समय धरना दिया।

संसद की प्रासंगिकता का प्रश्न छोड़ भी दें, तो कांग्रेस की अप्रासंगिकता और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य से उसका अवसान होते जाना शायद इस हफ़्ते की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है और इस अंतःस्राव को थामने वाला कोई नहीं है।

समतामूलक समाज में ही आर्थिक न्याय संभव

असमानता के आंकड़े

दीपिका अरोड़ा

आय व संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के चलते अधिकांश लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हाशिए पर पड़े वर्ग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, नौकरियों आदि तक अपेक्षित पहुंच नहीं बना पाते।भारत का नाम भले ही विश्व की सर्वाधिक तीव्रगति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है किंतु समानता के दृष्टिगत आज भी समाज में बृहद अंतर देखने को मिलता है। नवीनतम 'विश्व असमानता रिपोर्ट, 2026' की मानें तो, भारत की कुल संपत्ति का 65 प्रतिशत (लगभग दो-तिहाई) हिस्सा शीर्ष 10 फ़ीसदी अमीरों के पास केंद्रित है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 6.4 प्रतिशत संपत्ति है। महिला श्रम भागीदारी दर सिर्फ 15.7 प्रतिशत है।देश?के टॉप 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति है, जोकि 1961 के पश्चात सबसे ज्यादा आंकी गई। शीर्ष 10 प्रतिशत जहां राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत कमाते हैं, वहीं निम्न 50 प्रतिशत लोगों को केवल 15 प्रतिशत आय मिलती है। 2014 से 2024 के बीच टॉप 10 प्रतिशत तथा नीचे के 50 प्रतिशत के बीच आय का अंतर थोड़ा बढ़क??र, 38 प्रतिशत से 38.2 प्रतिशत हो गया।

आंकड़ों के तहत, भारत में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 6,200 यूरो तथा औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो है। रिपोर्ट भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में सम्मिलित करती है। असमानता दर, आर्थिक उदारीकरण के बाद तेज़ी से बढ़ी।

भारत सरकार के आंकड़े खंगालें तो अभी तक 41.32 प्रतिशत लोगों को आवास उपलब्ध नहीं। 31.52 प्रतिशत आबादी संतुलित पोषण से वंचित है हालांकि यही रिपोर्ट 24.82 करोड़ लोगों के ग़रीबी रेखा से ऊपर आने का दावा करती है।

उपभोक्ता बाजार के अनुसार, प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ना तथा अफोर्डेबल रियल एस्टेट सेगमेंट में गिरावट आना भी असमानता का सूचक है। आय व संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के चलते अधिकांश

लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हाशिए पर पड़े वर्ग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, नौकरियों आदि तक अपेक्षित पहुंच नहीं बना पाते।उन्नत व पिछड़े राज्यों के बीच विकास का अंतर भी असमानता बढ़ाता है। विस्थापन के चलते लोगों को अपनी आजीविका तथा अधिकारों से वंचित होना पड़ता है।

भूमि स्वामित्व में असमानता तथा कृषि में अक्षमताएं ग्रामीण आय पर प्रभाव डालती हैं। पिछड़े क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच न होने से स्थानीय निवासियों की कमाई की क्षमता सिमटती है। देश की आबादी का एक बड़ा अंश कम मजदूरी तथा अस्थिर रोजगार वाले असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। कुशल व अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन का भारी अंतर देखा गया। कई लोग अपनी योग्यता से कम काम करते हैं, जिसका उत्पादकता व आय, दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

वैश्वीकरण से वास्तव में असमानता को भी बढ़ावा मिला। विनिर्माण क्षेत्र में बाधाओं तथा सेवा क्षेत्र के लाभ कुछेक वर्गों तक सीमित होने की वज़ह से लाखों लोगों को रोज़ग़ार नहीं मिल पाता।

अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता जहां गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालती है, वहीं असंगठित क्षेत्रों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ख़ासकर आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें निम्न वर्ग की आय और भी कम कर देती हैं।भारत में आय असमानता के मुख्य कारकों में शिक्षा-स्वास्थ्य तक असमान पहुंच, रोज़ग़ार के अवसरों में अंतर, कौशल तथा वेतन में खाई, क्षेत्रीय असंतुलन, जाति-लिंग आधारित भेदभाव एवं धन का संकेंद्रण शामिल हैं। मुद्रास्फीति, अप्रभावी सरकारी नीतियों, सामाजिक न्याय के सिद्धांत लागू करने की विफलता, संसाधनों के वितरण व आर्थिक अवसरों में असमानता से अंतर और गहरा हो जाता है।भारत में असमानता एक जटिल तथा व्यापक समस्या बनी हुई है।

विशेषज्ञों के मुताबिक़, इस असंतुलन का आर्थिक व सामाजिक ढांचे, दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ज़ाहिर है, अमीर-गरीब के मध्य बढ़ती खाई न केवल देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करती है बल्कि समाज में अशांति, असंतोष, पारस्परिक द्वेष तथा संघर्ष को भी जन्म देती है। रिपोर्ट के तथ्य हमारे राजनीतिज्ञों के आर्थिक-सामाजिक समता संबंधी वे तमाम दावे ख़ारिज करते प्रतीत होते हैं, जिनके आधार पर वे चुनावी वोट बैंक भुनाते दिखाई पड़ते हैं।

दरअसल, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की अवधारणा 'समतापरक समाज' के निर्माण पर ही टिकी है। समतावादी समाज का मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना रहा कि समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव समान अधिकार, अवसर तथा संसाधन प्राप्त हों। विशेषज्ञ भारत में धन के पुनर्वितरण, टैक्स न्याय के लिए व्यापक संपत्ति कर तथा सुपर टैक्स जैसे उपायों की वकालत करते हैं। सुनियोजन द्वारा समाज में मौजूद व्यापक अंतर निश्चय ही पाटा जा सकता है।

माघ मेले को लेकर रेलवे का अलर्ट 10 ट्रेनें सूबेदारगंज से चलेंगी

सूबेदारगंज, फाफामऊ और छिवकी से होगी प्रमुख ट्रेनों की आवाजाही, कई ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी बदला

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। माघ मेले में यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के मद्देनज़र रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने 10 महत्वपूर्ण ट्रेनों का टर्मिनल बदल दिया है, साथ ही कुछ ट्रेनों को आंशिक निरस्त करने और मार्ग परिवर्तन किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। यह व्यवस्था 2 जनवरी से 17 फरवरी तक लागू रहेगी।ट्रेन संख्या 12417 प्रयागराजङ्कनई दिल्ली अब 2 जनवरी से 17 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन से रात 10:15 बजे रवाना होगी। वहीं

ट्रेन संख्या 12418 नई दिल्लीङ्कप्रयागराज 1 जनवरी से 16 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन पर सुबह 6-55 बजे पहुंचेगी।

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 12403 प्रयागराज–लालगढ़ 2 जनवरी से 17 फरवरी तक सूबेदारगंज से 11:15 बजे चलेगी। ट्रेन संख्या 22438 आनंद विहार टर्मिनल–प्रयागराज, 12 से 24 जनवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन पर सुबह 6:15 बजे पहुंचेगी।नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जोगबनी–बाड़मेर–हावड़ा सुपरफास्ट, आनंद विहार टर्मिनल–जोगबनी एक्सप्रेस, नई दिल्लीङ्कहावड़ा राजधानी और हावड़ा–बाड़मेर सुपरफास्ट ट्रेनों को भी प्रयागराज की बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर विभिन्न तिथियों में रोका जाएगा।

इसके अलावा प्रयागराज–गोरखपुर ट्रेन 13 से 25 जनवरी तक फाफामऊ स्टेशन से दोपहर 3:35 बजे चलेगी, जबकि वापसी में गोरखपुर–प्रयागराज इसी अवधि में फाफामऊ पर 12:55 बजे पहुंचेगी।चोपन–प्रयागराज ट्रेन 2 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 12:55 बजे आएगी, जबकि प्रयागराज–चोपन ट्रेन 15 से 17 फरवरी के बीच छिवकी स्टेशन से 3:15 बजे रवाना होगी।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने स्टेशन और समय की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को 3 साल की सजा

» गजनेर पुलिस की सशक्त पैरवी से दोषी को मिली सजा

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' और 'मिशन शक्ति–5' अभियान को बड़ी सफलता मिली। अपर जिला जज – 13 (पॉक्सो एक्ट) ने गजनेर थाना क्षेत्र के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी रामू को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला 2 जुलाई 2019 का है, जब गजनेर के ग्राम ररुआ निवासी अभियुक्त रामू ने घर में सो रही एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के बाद मात्र एक माह के भीतर 1 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था।

प्रभावी पैरवी से मिली सजा

पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने रामू को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अर्थदंड न भरने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह सजा समाज में कड़ा संदेश देगी और महिला संबंधी अपराधों को रोकने में मददगार साबित होगी।

बाइक को बचाने के चक्कर में ई रिक्शा पलटा, चार घायल

एक की हालत नाजुक,भेजा गया हैलट अस्पताल

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के असालतगंज स्थित बिरहुन रोड पर सिरसैयन पुरवा मोड़ के पास बाइक को बचाने के चक्कर में एक ई रिक्शा के अनियंत्रित होकर पलट गया। उसमें सवार चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए।घायलों में से एक की हालत गंभीर देख उसे रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के पश्चात कानपुर हैलट रेफर किया गया है।घायलों की पहचान मुस्तकीम खान ,कमरजहां ,रफीक सिद्दीकी और तबस्सुम के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी घायलों को रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक एन चंद्रा ने उनका उपचार किया।गंभीर रूप से घायल मुस्तकीम खान की हालत नाजुक देख उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घायल चालक रफीक सिद्दीकी ने बताया कि वह ई रिक्शा से अपने परिवार के सदस्यों को लेकर बिरहुन में अपनी भांजी की शादी में शामिल होने जा रहा था।तभी रास्ते में एक बाइक को बचाने के चक्कर में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया।

रायबरेली: समीक्षा बैठक में एसपी ने लगाई पुलिस अफसरों की क्लास

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रायबरेली-जनपद की धरती में तैनात तेजतर्रार छवि के न्यायप्रिय पुलिस अधीक्षक डॉ०यशवीर सिंह ने सभी क्षेत्राधिकारियों और प्रभारी निरीक्षकों व थाना प्रभारियों के साथ कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कार्यकाल स्थित किरण बहुद्देशीय हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।इसमें कानून एवं शांति व्यवस्था,अपराध नियंत्रण व आगामी त्यौहारों आदि के संबन्ध में समीक्षा कर सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

» एसपी ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गम्भीर अपराधों, हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट,लुट आदि अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जाए

एसपी डॉ०यशवीर सिंह ने कहा कि आगामी त्यौहारों एवं नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए।सभी क्षेत्राधिकारी और थाना थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को एकदम चुस्त-दुरुस्त रखें।किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने महिला एवं बाल अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाई करने,पुरुस्कार घोषित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने,झाड़ फूंक के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं,फर्जी जमानतदारों,सूदखोरों,अवैध शराब,मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी तथा जुआ-सट्टा जैसे गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों,फर्जी खाते खोलने व फर्जी सिम बेचने वालों को चिन्हीकरण कर कठोर कार्यवाही एवं शातिर अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने,गुंडा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर की कार्रवाई आदि के लिए निर्देशित किया।एसपी ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गम्भीर अपराधों,हत्या,दुष्कर्म,पॉक्सो एक्ट,लुट आदि अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाने तथा चोरी,नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार करके प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।उन्होंने आगे कहा कि मार्च के महीने में होली का पर्व भी है जिसमें कहा कहा होली जलनी है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या-क्या विशेष आयोजन होते है इसके लिए क्षेत्रीय थाना प्रभारी सूची बनाएं और कोई नई परंपरा शुरू करने के लिए अनुमति न दें।इसके अलावा चोरियां रोकने के लिए रात्रि गश्त भी बढ़ाया जाएं।कानून व्यवस्था ठीक रखना सभी की जिम्मेदारी है और पूरी ईमानदारी,निष्ठा एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करें।बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा,समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी सहित सभी शाखा एवं कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे..

खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दम, विजेताओं को मिले उपहार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। खेलकूद शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ-साथ ध्यान केंद्रीकरण में सहायक है। इसके अलावा करियर को भी आसान बनाता है। परिषदीय विद्यालयों में इस प्रकार के आयोजन कराकर बच्चों को सर्वांगीण विकास से जोड़ा जा रहा है। यह बात खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कही। पी.एम.श्री विद्यालय बाढ़ापुर अकबरपुर कानपुर देहात में एनुअल स्पोर्ट्स डे धूम धाम से मनाया गया। जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की दौड़,प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के चारों हाउस महाराणा प्रताप हाउस, शिवा जी हाउस, अशोक हाउस,चाणक्य हाउस में जबदस्त प्रतियोगिता हुई। जिसमें शिवा जी हाउस ने बाजी मारी साथ ही बच्चों द्वारा बैट ड्रिल, योगा प्रेजेंटेशन,पॉम ने सभी अभिवावकों का दिल जीत लिया। चैंपियन टीम विजेता सोनाक्षी निक्की दीक्षिता,अंजलि ने ट्रॉफ़ी पर लगातार दूसरी बार अधिकार जमाया। खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया व बच्चों को मेडल पहनाया गया

तथा बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में एसआरजी संत कुमार दीक्षित,एआरपी अमित तिवारी, ज्ञान बाबू, महाराज सिंह, सभासद अमृता कुशवाहा एसएमसी अध्यक्ष गुड्डू श्रीवास्तव विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कंचन यादव, सुमन यादव सुरेखा यादव, दिनेश चन्द पाठक दिव्या सक्सेना,उमा देवी समस्त आंगनवाड़ी की महिलाएं सहित अन्य अभिभावक उपस्थित रहे।

थाने के नीचे ज्वेलरी शॉप में चोरी का प्रयास

» तिजोरी न खुलने पर लौटे चोर, बाहर रखे एक हार को ले गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बेखौफ चोरों ने दो दुकानों पर धावा बोल चोरी का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा लेकिन एक सोने का हार लेकर मौके से फरार हो गए। सुबह दुकान को खुला देख स्थानीय लोगों ने व्यापारी को सूचना दी। वहीं इस घटना से व्यापारियों में दहशत है। जनपद के झींझक कस्बे के रहने वाले अंकित गुप्ता रसूलाबाद कस्बे में तहसील व थाना के नीचे बिल्हौर मार्ग पर जय शोभन सरकार नाम से ज्वेलरी शॉप किए हुए हैं। मंगलवार रात वह अपनी दुकान बंद करके वापस झींझक चले गए। तभी आधी रात को अज्ञात चोरों ने उनकी ज्वेलरी शॉप में शटर का ताला तोड़कर उन्होंने तिजोरी खोलने का प्रयास किया लेकिन नहीं खोल सके। वहीं इसके अलावा चोरों ने उनकी दुकान से चंद कदम की दूरी पर पंकज शुक्ला की साड़ी की दुकान के शटर का भी ताला तोड़ दिया। हालांकि वह कुछ ले जाने में नाकामयाब रहे।

चोरों ने शंकर मार्केट में रहने वाले मार्केट मलिक के घर के बाहर से कुंडी भी लगा दी ताकि चोरी की वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सके। सुबह जब व्यापारियों को उक्त घटना के विषय में जानकारी हुई तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया व्यापारियों ने गशत व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित व्यापारियों ने थाने में तहरीर देकर चोरी की घटना का खुलासा किए जाने एवं व्यापारियों की दुकानों की सुरक्षा मुहैय्या कराए जाने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही दुकानों को बारीकी से देखा और बताया जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

संदिग्ध हालात में युवक ने पेड़ से लटककर की आत्महत्या

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के भिल्सी गांव में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में नीम के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की। मृतक की पहचान घाटमपुर कानपुर नगर के कंठीपुर गांव निवासी छेदीलाल के 23 वर्षीय पुत्र अखिलेश के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह,चौकी प्रभारी पामा एस आई शोभित कटियार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सूचना परिजनों को दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्या मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हसनापुर ग्राम प्रधान पर होगी एफआईआर!

» ग्राम प्रधान ने अपने और सगे संबंधियों के नाम पर बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई लाखों की ग्राम विकास निधि

» खडंजा, नाली निर्माण, हैंडपंप मरम्मत सहित कई अन्य मदों पर खर्च दिखाकर किया गया सरकारी धन का बंदरबांट

» अकबरपुर ब्लाक के हसनापुर ग्राम पंचायत के कई बिल बाउचर सोशल मीडिया पर वायरल

ग्राम प्रधान राम सिंह यादव और ग्राम सचिव को जारी स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिया गया

स्वराज इंडिया
कानपुर देहात : ग्राम प्रधान ने 'लूट' ली ग्राम सभा की विकास निधि

स्वराज इंडिया
ग्राम पंचायत हसनापुर
कानपुर देहात: तत्कालीन ग्राम सचिव आशिका प्रधान ने किया बंटाधार

नोटिस
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, अकबरपुर, कानपुर देहात।
/दैनिक समा0/2025-26
ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत हसनापुर
विकास खण्ड अकबरपुर
जनपद कानपुर देहात
सहायक विकास अधिकारी (पं)
अकबरपुर कानपुर देहात

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार भले ही जीरो टालरेंस नीति का डंका बजा रही हो लेकिन ब्लाक से लेकर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले में भरे पडे हैं। इनकी सही से जांच करवाई जाए तो बडी धांधलियां सामने आ सकती है। अकबरपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत हसनापुर के कई बिल बाउचर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लाखों की हेराफेरी उजागर हुई। इस प्रकरण में स्वराज इंडिया ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इसपर उच्चाधिकारियों ने संज्ञान लेकर जांच पडताल कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सीडीओ एन लक्ष्मी के निर्देश पर अकबरपुर ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी आदित्य शुक्ला ने 10 दिसंबर 2025 को ग्राम प्रधान राम सिंह यादव और ग्राम सचिव को पत्र जारी करके सरकारी निधि की राशि अपने खातों में ट्रांसफर को लेकर बिंदुवार जवाब तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

ग्राम पंचायत की वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव शशि बाजपेई ने बताया कि मै यहां पर ग्राम सचिव के तौर पर अगस्त सितंबर में आई हूं, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। मामला पुराना है इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को जल्द भेजेंगे। वहीं, ग्राम प्रधान राम सिंह यादव पर सरकारी धन गबन के गंभीर आरोप हैं, मामले में वह घिरते जा रहे हैं। इनपर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ग्राम पंचायत पोर्टल से जारी स्क्रीन शॉट के अनुसार वर्ष 2023-2024 में 1 जून 2023 को ग्राम प्रधान के खाते में 21 हजार 5 सौ का भुगतान साफ सफाई के लिए दिखाया गया है। 6 अगस्त 2023 को प्राथमिक विद्यालय ठकुरनगढेवा में शौचालय निर्माण के लिए 17 हजार 410 का भुगतान किया गया है। 31 दिसबंर 2022 को जगद सिंह के घर से मेवालाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में 29 हजार 930 रूपए का भुगतान ग्राम प्रधान के खाते में किया गया है। 6 अगस्त 2023 को हैंडपंप मरम्मत के नाम पर 5400 का भुगतान लिया गया है। इस तरह से कई अन्य भुगतान हैं जिनको नाते रिश्तेदारों के खाते में डलवाकर हडपा गया है। वहीं, गांव वालों की तरफ से शपथपत्र में शिकायत की तैयारी की जा रही है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने गांव के विकास के लिए आई धनराशि का बंदरबांट किया है।

डीएम कपिल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, कई पंचायतों की जांच के लिए टीम गठित की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।

शिक्षक संकुल बैठक में निपुण लक्ष्य प्राप्त करने पर चर्चा

» एआरपी ने कई बिंदुओं पर दिए दिशा निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वशिक्षा अभियान योजना के तहत निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकासखंड मलासा के पुलंदर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक संकुल की मासिक बैठक की गई। बैठक का शुभारंभ नोडल शिक्षक मनोज मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा एआरपी अश्वनी कटियार ने प्रेरणा गीत के माध्यम से किया। यह बैठक जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार की गई।

बैठक के दौरान एआरपी अश्वनी कटियार ने निपुण विद्यालय, निपुण जनपद की बारीकियों को समझाया।साथ ही साथ बच्चों को निपुण लक्ष्य एप के बारे में जानकारी दी।उन्होंने बताया कि भाषा और दक्षता में 75 प्रतिशत तथा निपुण आंकलन में 80 प्रतिशत स्कोर होने पर विद्यालय निपुण बनता है।

बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ड्रॉप आउट बच्चे, जीरो पावर्टी साक्षरता सर्वे, एनआईएलपी सर्वे, अपार आईडी आदि बिंदु शामिल हैं।बैठक में एजेंडा के अनुसार शिक्षकों को परियोजना संबंधी समस्त जानकारियों से अवगत कराया गया।नोडल शिक्षक मनोज मिश्रा ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि चर्चा परिचर्चा में जो भी कुछ सीखा गया है और परियोजना के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए।

उन्होंने शिक्षकों से अपने विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करने का आग्रह किया।उन्होंने डायरी नियमित भरने और पाठ योजना बनाकर ही शिक्षण कार्य करने पर जोर दिया।बैठक में प्रधानाध्यापक ने सभी शिक्षकों का धन्यवाद और आभार प्रगट किया।

इस मौके पर शैलेन्द्र सचान, दशरथ, वेद प्रकाश, प्रदीप, संजय मिश्रा, मोहित, संगीता, दीपा मौर्या, भावना कन्नौजिया, प्रतिमा, सोनी,रेखा, निधि आदि शिक्षक,शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 । Email: swarajindia2023@gmail.com । Mob: 7800009853, । Website: www.swarajindianews.com । (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

सरवनखेड़ा क्षेत्र पंचायत बैठक में 3.16 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति

सभी स्वीकृत कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात माती।ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरवनखेड़ा क्षेत्र पंचायत की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 3.16 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में गांवों की प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख उर्वशी सिंह चंदेल ने की। उन्होंने कहा कि पंचायत का लक्ष्य विकास योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से धरातल पर उतारना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता बरती जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाए। बैठक में सड़क, नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण व मरम्मत से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सभी स्वीकृत कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और गुणवत्ता मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कराए जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के कायाकल्प और अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

पंचायत सदस्यों ने गांवों में जल निकासी, खराब सड़कों, हैंडपंप मरम्मत और अन्य स्थानीय समस्याएं उठाईं। इस पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख उर्वशी सिंह चंदेल ने संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि विकास कार्यों में जनहित सर्वोपरि रहेगा और पंचायत ग्रामीणों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।

कोहरे की चादर, शीतलहर से जनजीवन बेहाल

» सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमने से सन्नाटा

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात माती। कोहरे के साथ चली शीतलहर ने सरवनखेड़ा क्षेत्र में जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जहां आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई, वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई। बुधवार की सुबह कोहरे की घनी चादर के साथ हुई, जिससे देर सुबह तक दृश्यता बेहद कम बनी रही और नजदीक की वस्तुएं तक साफ दिखाई नहीं दे सकीं।

शीतलहर के चलते गजनेरङ्करायपुर मार्ग पर वाहनों को धीमी गति से चलना पड़ा। चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा, जिससे आवागमन प्रभावित रहा। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव के पास बैठकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आए। बाजारों और चौराहों पर भी ठंड का असर साफ दिखाई दिया, जहां आम दिनों की तुलना में चहल-पहल कम रही।भीषण ठंड का सबसे ज्यादा असर बेजुबान पशु-पक्षियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंड से बचने के लिए आवारा पशु और कुत्ते सड़कों के किनारे, दुकानों के सामने और रिहायशी इलाकों में एक-दूसरे से सटकर बैठे नजर आए। गांवों में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी भारी कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद ठंड से कंपकपाते नजर आए। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, जबकि बुजुर्गों और बीमार लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण सर्द हवाओं ने ठंड का अहसास और तीखा कर दिया है।मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर शीतलहर से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग प्रशासन से अलाव, रैन बसेरों और बेजुबान पशुओं के लिए भी ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इस भीषण सर्दी में किसी को परेशानी न झेलनी पड़े।

डंपर की टक्कर से बाइक सवार घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लालपुर चौकी के पास कानपुर झांसी हाइवे पर एक अज्ञात डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान वाराणसी जिले के चितई थाना क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी अरुण कुमार के 21 वर्षीय पुत्र तिलक कुमार के रूप में हुई है।वह अपनी बाइक से झांसी से वाराणसी की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना एंबुलेंस और पुलिस को दी। कोतवाल हरमीत सिंह ने बताया कि घायल को अस्पताल भेजा गया है। फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है।

गजनेर में जला अलाव सरवनखेड़ा अब भी ठिठुर रहा

» शीतलहर में उजागर हुई व्यवस्था की सच्चाई

» स्वराज इंडिया न्यूज

हलचल खबर का असर

कानपुर देहात माती। शीतलहर के प्रकोप के बीच गजनेर और सरवनखेडा चौराहों पर अलाव की व्यवस्था न होने को लेकर स्वराज इंडिया में प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में तो आया, लेकिन उसकी संवेदनशीलता आधी-अधूरी ही नजर आई। गजनेर चौराहे पर तो अलाव जला दिया गया, मगर सरवनखेड़ा चौराहा अब भी प्रशासनिक उपेक्षा से ठिठुरता नजर आ रहा है।

गजनेर चौराहे पर अलाव जलने से राहगीरों, दिहाड़ी मजदूरों, ठेला-पटरी दुकानदारों और बुजुर्गों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सरवनखेड़ा चौराहे पर हालात जस के तस बने हुए हैं। यहां आज भी लोग मजबूरी में घास-फूस, लकड़ी और कूड़ा-कचरा जलाकर सर्दी से बचने का जुगाड़ कर रहे हैं। यह नजारा प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब शीतलहर पूरे जिले को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, तो राहत भी समान रूप से मिलनी चाहिए। सरवनखेड़ा चौराहा जनपद के सबसे व्यस्त इलाकों में गिना जाता है, जहां सुबह से देर रात तक भारी आवागमन रहता है। इसके बावजूद यहां अलाव न जलाया जाना प्रशासनिक उदासीनता है।

क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि समान व्यवस्था की जाए। केवल गजनेर में अलाव जलाकर जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ा जाए, बल्कि सरवनखेड़ा सहित सभी प्रमुख चौराहों पर तत्काल और नियमित रूप से अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।अब सवाल यह नहीं है कि अलाव जला या नहीं, सवाल यह है कि प्रशासन ठंड से जूझ रहे आमजन को कब तक आधी राहत देकर बहलाता रहेगा।

स्वराज इंडिया
कानपुर देहात

गजनेर व सरवनखेड़ा के चौराहों पर हो रहा अलाव का इंतजार

नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का मामला

छात्र-छात्रा की पहचान, वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर बर्खास्त, तीन पर मुकदमा दर्ज

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गाजियाबाद। नमो भारत रैपिड रेल में अश्लील हरकत करने वाले छात्र और छात्रा की पहचान कर ली गई है। दोनों के खिलाफ गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, वीडियो वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर पर भी केस दर्ज कर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों छात्र मेरठ के अलग-अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। छात्रा दुहाई स्थित एक कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई कर रही है, जबकि छात्र राजनगर एक्सटेंशन के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों कॉलेजों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। घटना के बाद से दोनों छात्र कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

यह मामला 24 नवंबर का है, जब दिल्ली से मेरठ के बीच चल रही नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में छात्र-छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पूरी घटना ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के समय कोच में अन्य यात्री भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया।

डीबीआरआरटीएस के सुरक्षा प्रमुख की ओर से 22 दिसंबर को मुरादनगर थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि 24 नवंबर को शाम करीब चार बजे दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही ट्रेन के प्रीमियम कोच नंबर तेईस में अश्लील कृत्य हुआ।

जांच में सामने आया कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने बिना अनुमति और बिना सूचना के केबिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जो कंपनी के नियमों का सीधा उल्लंघन है। उसी ऑपरेटर ने वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल किया। इसके बाद तीन दिसंबर को उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

पुलिस और एनसीआरटीसी का बयान

गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि ट्रेन अधिकारियों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सभी साक्ष्यों को जांच में शामिल कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नमो भारत रैपिड रेल की प्रमुख सुविधाएं

नमो भारत ट्रेन को एक सौ अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि वर्तमान में यह एक सौ साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित हो रही है। यह देश की सबसे तेज रफ्तार रेल सेवाओं में शामिल है।

ट्रेन में कुल छह कोच हैं, जिनमें एक प्रीमियम कोच और एक महिला आरक्षित कोच शामिल है। एक ट्रेन में लगभग सत्रह सौ यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, लगेज रैक और डिजिटल रूट मैप उपलब्ध हैं।महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीटें आरक्षित हैं। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर रखने की भी सुविधा है। प्रीमियम कोच में आरामदायक रिक्लाइनिंग सीटें और अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं।स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक से लैस जांच व्यवस्था और डबल सुरक्षा प्रणाली लागू है।

एनसीआरटीसी के जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने कहा कि नमो भारत ट्रेनों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाएगा। वीडियो वायरल करने वाले कर्मचारी की पहचान कर उसे निष्कासित कर दिया गया है।

सोती रही पुलिस, 25 हजार का इनामी बदमाश अस्पताल से फरार

- » मुठभेड़ में घायल होने के बाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती
- » दरोगा समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित, आरोपी की तलाश में कई टीमें जुटीं

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

प्रतापगढ़। पुलिस की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई, जब सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के मामले में पकड़ा गया 25 हजार का इनामी जावेद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। मंगलवार देर रात मुठभेड़ में गोली लगने से घायल जावेद को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन बुधवार भोर करीब चार बजे वह मौके पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को सोता देख अस्पताल से भाग निकला। घटना सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ने गंभीर लापरवाही बरतने पर सुरक्षा में तैनात एक दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उड़ैयाडीह बाजार में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में जावेद पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तारी से पहले वह फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस और एसओजी टीम उसकी तलाश में जुटी थी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इससे पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस आरोपी के खिलाफ कुछ दिन पहले व्यापारी सड़क पर उतरे थे, वही आरोपी अब फिर पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं।

यूपी की सियासत में जातीय संतुलन की नई हलचल

ब्राह्मण विधायकों की बैठक से बढ़ी सरगर्मी, राजनीतिक दलों में चर्चा

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ताधारी खेमे के भीतर जातीय शक्ति संतुलन को लेकर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक अहम बैठक ने सियासी गलियारों से लेकर आम चर्चाओं तक नई बहस छेड़ दी है।यह बैठक लखनऊ में कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के आवास पर आयोजित हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में कुल 46 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। भोजन में पारंपरिक लिट्टी-चोखा की व्यवस्था की गई थी, जबकि मंगलवार के व्रत को देखते हुए फलाहार का भी इंतजाम किया गया। बैठक में नृपेंद्र मिश्र के पुत्र और विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्र की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही।बैठक में जिन प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही, उनमें रत्नाकर मिश्र, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र,

शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दूबे, राकेश गोस्वामी, रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडेय, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, बाबूलाल तिवारी, विनय द्विवेदी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रेमनारायण पांडेय, ज्ञान तिवारी, सुनील दत्त द्विवेदी और धर्मेंद्र सिंह भूमिहार शामिल बताए जा रहे हैं।

प्रदेश में कुल 52 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य हैं, जिनमें से 46 सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ठाकुर विधायकों का एक जुटान हुआ था, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। उस सम्मेलन में सत्ताधारी दल के साथ-साथ अन्य दलों के ठाकुर विधायक भी शामिल हुए थे। उस समय इसे पारिवारिक मिलन बताया गया था, लेकिन इसके बाद से ही ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब ब्राह्मण विधायकों की यह बैठक उसी पिछले शक्ति प्रदर्शन का जवाब मानी जा रही है। आने वाले चुनावी माहौल में इस तरह की बैठकों से सत्ताधारी दल के भीतर जातीय समीकरण और नेतृत्व संतुलन को लेकर सियासत और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

अयोध्या

खेल के मैदान में

अचानक चली मौत की गोली

तिहरा माझा में 16 साल के आलोक की खेलते समय हत्या

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। मंगलवार शाम तिहरा माझा गांव में खेल का मैदान अचानक कत्लगाह में बदल गया। कक्षा नौ में पढ़ने वाला 16 वर्षीय आलोक वर्मा उर्फ सन्नी उस वक्त मौत के मुंह में चला गया, जब वह गांव के कुछ युवकों के साथ खेल रहा था। अचानक चली गोली ने उसकी मासूम जिंदगी छीन ली। पेट में लगी गोली ने न सिर्फ एक किशोर को मार डाला, बल्कि पूरे गांव को सदमे में डुबो दिया।

परिजनों के मुताबिक शाम करीब चार बजे आलोक गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक गोली चली और सीधे उसके पेट में जा धंसी। चीख-पुकार मच गई। लहूलुहान आलोक को परिजन आनन-फानन में दशरथ मेडिकल कॉलेज, अयोध्या लेकर पहुंचे। हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया।लखनऊ ले जाते समय रौनाही टोल प्लाजा के पास आलोक की हालत और बिगड़ गई। मजबूरी में उसे सोहावल सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक मां की आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा बेटा दम तोड़ गया। मृतक की मां ने गांव के ही युवक अनीश यादव पुत्र अंगद यादव पर जानबूझकर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ग्रामीणों से जानकारी करते पुलिस अधिकारी

कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला अवैध असलहे से गोली चलने का सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। आलोक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। अब परिवार में मां, एक छोटा भाई और एक बहन रह गए हैं। घर की उम्मीद, मां का सहारा सब कुछ एक गोली ने छीन लिया। घटना के बाद पूरे तिहरा माझा गांव में मातम पसरा है। सवाल यह है कि अवैध हथियार गांव तक कैसे पहुंच रहे हैं? खेलते बच्चों के हाथों में बंदूकें और गोलियां कौन दे रहा है? पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश हो रही है।

प्रभु राम को रत्नजड़ित भक्ति का विराट प्रणाम

रामनगरी अयोध्या को कर्नाटक के गुमनाम भक्त का 30 करोड़ का अनमोल उपहार

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। राम की नगरी में आस्था कोई शब्द नहीं, वह परंपरा है; कोई क्षण नहीं, वह अनंत यात्रा है। इसी सनातन यात्रा में मंगलवार की शाम एक ऐसा अध्याय जुड़ गया, जिसने अयोध्या ही नहीं, पूरे भारत की धार्मिक चेतना को भाव-विभोर कर दिया। कर्नाटक के एक गुमनाम रामभक्त ने श्रीराम जन्मभूमि परिसर को ऐसा भव्य उपहार अर्पित किया है, जिसकी आभा सोने से कहीं आगे श्रद्धा, समर्पण और सनातन संस्कारों की चमक से दमकती है।करीब 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी यह विराट प्रतिमा केवल धातु और रत्नों का संयोजन नहीं, बल्कि भक्ति की मूर्त अभिव्यक्ति है। हीरे, पन्ने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी यह कृति करोड़ों की कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान इसलिए है क्योंकि यह निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपये है, पर आस्थावान हृदय के लिए इसका मूल्य अनमाप्य है। दक्षिण भारतीय शिल्पकला शैली में निर्मित इस प्रतिमा ने यह सिद्ध कर दिया कि राम उत्तर या दक्षिण के नहीं समूचे भारत के हैं। सूत्र बताते हैं कि तंजावुर के अनुभवी कारीगरों ने महीनों की साधना और साधन से इस प्रतिमा को आकार दिया। किस धातु का प्रयोग हुआ है यह अभी रहस्य है, पर उसकी आभा स्वयं उत्तर देती है।

विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक खास वैन से यह प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या पहुंची। 5ड़6 दिनों में 1,750 किलोमीटर का सफर—यह केवल दूरी नहीं, भक्ति की तपस्या थी। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे राम मंदिर परिसर में इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया, और उसी क्षण अयोध्या की हवाओं में उत्सव घुल गया।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के डॉ. अनिल मिश्र के अनुसार, प्रतिमा का अनुमानित वजन लगभग 5 क्विंटल है। सटीक मापन की प्रक्रिया जारी है। प्रस्ताव है कि इसे संत तुलसीदास मंदिर के निकट अंगद टीला पर स्थापित किया जाए। स्थापना से पूर्व भव्य अनावरण समारोह होगा, जिसमें देशभर के संत-महात्माओं के आमंत्रण की तैयारी है।इस उपहार का सबसे बड़ा सौंदर्य इसका गुमनामी में किया गया दान है। न नाम, न यश केवल राम। यह वही सनातन परंपरा है, जहाँ कर्ता पीछे रह जाता है और कृत्य अमर हो जाता है। यह केवल एक खबर नहीं, सनातन चेतना का साक्ष्य है कि रामराज्य की कल्पना आज भी जीवित है । अयोध्या आज भी आस्था का ध्रुवतारा है और भारत की आत्मा आज भी कहकर एक हो जाती है।

किसानों का विकास के साथ दिया पर्यावरण का संदेश

» कृषि मेले में बच्चों की प्रस्तुति ने सबका मन मोहा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। श्री परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, विद्याकुंड अयोध्या में कृषि मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रामाय ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं महाविद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती वंदना उपाध्याय रहीं। उन्होंने छात्र-छात्राओं द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर बच्चों से संवाद किया और कृषि के क्षेत्र में नवाचार व विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का विकास ही देश का विकास है।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किया गया, जिन्होंने अपना जीवन किसानों के अधिकारों और ग्रामीण विकास को समर्पित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार तिवारी ने कहा कि कृषि मेले में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया नजारा सराहनीय है। प्रदर्शनी का उद्देश्य उन्नत फसल उत्पादन, आधुनिक कृषि तकनीक और फसल प्रबंधन की जानकारी देना है। कृषि विभागाध्यक्ष डॉ. आर.आर. यादव ने बताया कि छात्रों के स्टाल युवा पीढ़ी में कृषि के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं।

कट्टरपंथ और चरमपंथ की गिरफ्त में बांग्लादेश

» देश में हालात बदतर, अखबार के दफ्तर और हिन्दू परिवारों को बनाया जा रहा निशाना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। बांग्लादेश इस समय भीषण अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें इतनी हावी हो चुकी हैं कि पुलिस और सेना भी कई जगहों पर बेबस नजर आ रही हैं। हालिया घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि उपद्रवी भीड़ के सामने सरकारी सुरक्षा तंत्र की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। ताजा घटनाक्रम में राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में कट्टरपंथी भीड़ ने खुलेआम हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात इतने गंभीर हो गए कि बांग्लादेशी सेना को पत्रकारों और आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए केवल बीस मिनट तक सुरक्षा देने की बात कहनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जब डेली स्टार अखबार के दफ्तर पर उपद्रवी हमला कर रहे थे और आग लगाने की तैयारी थी, तब सेना की प्राथमिकता भीड़ को रोकने के बजाय वहां फंसे पत्रकारों की जान बचाना रह गई।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो ने इन हमलों को पत्रकारिता पर सीधा हमला बताया है। डेली स्टार ने अपने बयान में कहा कि दफ्तर में हुई तोड़फोड़, लूटपाट और धमकियों के बावजूद वह न झुकेगा और न ही चुप रहेगा। हमलावरों ने दफ्तर से डेढ़ सौ से ज्यादा कंप्यूटर लूट लिए और सीसीटीवी तोड़ दिए, ताकि सबूत न बचें।

हिंसा का दायरा यहीं तक सीमित नहीं रहा। उपद्रवियों ने विपक्षी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े एक नेता के घर पर भी हमला किया और आग लगा दी। इस घटना में एक

मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई। इस घटना ने साफ कर दिया कि हिंसा अब राजनीतिक दुश्मनी और निजी प्रतिशोध का रूप ले चुकी है।

कट्टरपंथी हिंसा से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में भी गहरा डर है। मंदिरों, घरों और बस्तियों पर हमलों की खबरों ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कट्टरपंथी समूहों को सरकार का परोक्ष संरक्षण मिला हुआ है, इसी कारण वे बेलगाम हो गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए देशव्यापी सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कभी भी हिंसक हो सकते हैं। ब्रिटेन समेत अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच भारत ने भी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है।

खुफिया रिपोर्टों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में भड़क रही आग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की भूमिका हो सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक हाल के महीनों में हुई उच्चस्तरीय मुलाकातों के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेटवर्क को सक्रिय किया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कुल मिलाकर बांग्लादेश इस वक्त कट्टरपंथ और चरमपंथ की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। पत्रकारिता पर हमले, अल्पसंख्यकों में भय, विपक्ष पर हिंसा और सुरक्षा एजेंसियों की सीमित भूमिका ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात अगर जल्द नहीं संभले तो यह संकट और गहराने की आशंका जताई जा रही है।

अमेरिका में विदेशी ड्रोन बैन !

ट्रंप प्रशासन की सख्ती के बाद फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने सभी नए विदेशी ड्रोन मॉडल्स के वितरण पर रोक लगा दी है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विदेशी ड्रोन पर बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने सभी नए विदेशी ड्रोन मॉडल्स के वितरण पर रोक लगा दी है, जबकि पुराने मॉडलों को इस्तेमाल करने की अनुमति बनी रहेगी।डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तकनीकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए विदेशी ड्रोन्स पर शिकंजा कस दिया है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं' का हवाला देते हुए अमेरिका में सभी नए विदेशी ड्रोन मॉडल्स के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर मशहूर चीनी ड्रोन कंपनी डीजेआई पर पड़ने वाला है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो अमेरिकी नागरिक पहले से पुराने विदेशी ड्रोन मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे उन्हें उड़ाना जारी रख सकते हैं। यह प्रतिबंध केवल नए मॉडल्स पर लागू होगा। एफसीसी ने एक फैक्ट शीट में दावा किया कि फ्अपराधी, विदेशी दुश्मन और आतंकवादीफ् इन ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने में कर सकते हैं।

एजेंसी ने अपनी 'कवर्ड लिस्ट' को अपडेट किया है। यह उन उत्पादों की सूची है जिन्हें देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'अस्वीकार्य जोखिम' माना जाता है। अब इस लिस्ट में विदेश में निर्मित सभी 'यूएएस (अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम) और उनके महत्वपूर्ण घटकों' को शामिल कर लिया गया है।'

अमेरिकन ड्रोन डोमिनेंस' की तैयारीफेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन, ब्रेंडन कैर ने सोमवार को इस नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इस राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि स्नष्टष्ट ने अब विदेशी ड्रोन और उससे जुड़े घटकों को अपनी कवर्ड लिस्ट में जोड़ दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का पालन करते हुए, स्नष्टष्ट अमेरिकी ड्रोन निर्माताओं के साथ मिलकर काम करेगा ताकि 'अमेरिकन ड्रोन डोमिनेंस' को कायम किया जा सके।

चीनी कंपनियों पर पड़ेगा सबसे गहरा असर

यह नया नियम कई विदेशी कंपनियों को प्रभावित करेगा, लेकिन यह चीनी ड्रोन निर्माता DJI के लिए एक बड़ा झटका है। DJI को वर्तमान में दुनिया भर में और अमेरिका में ड्रोन बिक्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है।

कंपनी ने कहा कि इस फैसले तक पहुंचने के लिए किस जानकारी का उपयोग किया गया, इसका कोई डाटा जारी नहीं किया गया है। DJI ने दावा किया कि उनके उत्पाद बाजार में सबसे सुरक्षित हैं और वे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए एक खुले और प्रतिस्पर्धी बाजार की वकालत करते रहेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान चीनी कंपनियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाया है। इस नए ड्रोन बैन की नींव जून में पारित एक कार्यकारी आदेश के साथ रखी गई थी। इसका उद्देश्य अमेरिका में बने ड्रोन के उत्पादन को बढ़ावा देना और अमेरिकी ड्रोन सप्लाई चेन को विदेशी नियंत्रण से सुरक्षित रखना है।